

# भारत-नेपाल के अर्थशास्त्रीय और व्यापारिक दृष्टिकोण का समीक्षात्मक अध्ययन

बीज शब्द :

नेपाल की आर्थिक नीतियाँ, नेपाल के मुख्य उद्योग, भारत के नेपाल के साथ आर्थिक सहयोग, भारत नेपाल द्विपक्षीय व्यापार

ISSN 0975 1254 (PRINT)  
ISSN 2249-9180 (ONLINE)  
www.shodh.net

A Refereed Research Journal  
And a complete Periodical dedicated to  
Humanities & Social Science Research

शोध  
संचयन

एक देश की आर्थिक परिस्थितियाँ अन्य देशों को प्रभावित करती हैं और इन्हीं कारणों से अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों का निर्माण होता है। दो पड़ोसी देशों के सामाजिक राजनैतिक संबंधों के कारणों में आर्थिक तत्वों का विशेष महत्व होता है। भारत और नेपाल के बीच आर्थिक गतिशीलता के लिए अनेक संधियाँ हुई हैं। इनके आलोक में प्रस्तुत आलेख में भारत-नेपाल के बीच आर्थिक संधियाँ की गहत पड़ताल प्रस्तुत की गई है।

अत्यन्त दुःख के साथ सुचित करना पड़ रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से ब्रिजेश कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। शोध संचयन परिवार उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए इस दुःखद क्षण में इनके परिवार के साथ है।

ब्रिजेश कुमार  
असिस्टेंट प्रोफेसर,  
कामर्स विभाग,  
महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
जंगल धूसड़, गोरखपुर,  
उत्तर प्रदेश।

आधुनिक युग में कोई भी राज्य पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने का दावा नहीं कर सकता। विश्व का प्रत्येक राज्य किसी न किसी रूप में दूसरे राज्य पर निर्भर रहता है। एक देश की आर्थिक परिस्थितियाँ अन्य देश को प्रभावित करती हैं और इन्हीं कारणों से अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों का निर्माण होता है। यह सर्वविदित है कि प्रत्येक देश अपनी आर्थिक नीति का निर्माण अपने देश की समस्याओं को ध्यान में रखकर करता है। इस सन्दर्भ में जो भी आर्थिक नीति अपनायी जाती है उसका उद्देश्य राष्ट्रीय हितों को संरक्षित करना होता है। पामर एवं परकिंस ने लिखा है कि “राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए जब आर्थिक नीतियों का निर्माण किया जाता है। वे दूसरे राज्यों को हानि पहुँचाने के लिए हो या न हो, वे राष्ट्रीय नीति के आर्थिक साधन है।”<sup>1</sup>

आर्थिक नीतियों की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करते हुए पैडल फोर्ड और लिंकन ने लिखा है- “विदेश नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, प्रत्यक्ष या संबंधित रूप से कोई भी आर्थिक क्षमता, संस्था अथवा तकनीक को आर्थिक साधन कहते हैं।” जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इनका प्रयोग किया जाता है वे आर्थिक (जैसे आवश्यक कच्चे माल की प्राप्ति या निर्यात व्यापार में वृद्धि), राजनीति (कम विकसित राज्य में विकास या व्यवस्था परिवर्तन), सैनिक (अड्डों की प्राप्ति) अथवा मनोवैज्ञानिक (दूसरे राष्ट्र की नीति के प्रति सद्भावना या सहायता) हो सकते हैं।<sup>2</sup>

यदि हम स्वतंत्र भारत और नेपाल की विदेश नीतियों के सन्दर्भ में आर्थिक तत्व पर दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि विगत 65 वर्षों में दोनों देशों की विदेश नीतियों के निर्धारण में इस तत्व का भारी योगदान रहा है। आर्थिक दृष्टि से भारत का अधिकांश व्यापार पाश्चात्य देशों के साथ था। अपने भरपूर प्राकृतिक साधनों का पूर्ण सदुपयोग उन्हीं देशों की सहायता से सम्भव भी था। इस दृष्टिकोण से भारत के लिए सभी विकसित देशों के साथ मैत्री संबंध रखना आवश्यक था। इसी कारण भारत ने अपने को किसी भी सैनिक गुट में न बाँधते हुए सभी देशों से अधिकाधिक आर्थिक एवं तकनीक सहायता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की, इसका कारण स्पष्ट था कि भारत किसी प्रकार दूसरे गुट के प्रभाव क्षेत्र में न चला जाए। नेपाल की अर्थव्यवस्था भारत की तुलना में अत्यन्त लघु है, इस कारण उसे अपने आर्थिक संबंध अपने पड़ोसी देशों, विशेषकर भारत एवं चीन सहित अन्य एशियाई देशों से भी रखने होते हैं, क्योंकि भारत के साथ उसका संबंध अति प्राचीन है। उसकी भौतिक आर्थिक परिस्थितियाँ भारत के अनुकूल हैं। इस कारण नेपाल की आर्थिक प्रगति में सबसे अधिक योगदान भारत का रहता है।

## नेपाल के योजनाबद्ध विकास में भारत का योगदान-

योजना	कुल खर्च	विदेशी सहायता	प्रतिशत	भारतीय सहायता	प्रतिशत
प्रथम योजना	214.4	382.9	100	82.1	21.44
द्वितीय योजना	596.7	476.0	76	110.0	23.11
तृतीय योजना	1779.0	967.8	54	550.0	54.68
चतुर्थ योजना	3315.5	1508.9	46	563.6	37.36
पंचम योजना	8870.6	4240.8	48	643.6	15.18

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि योजनाबद्ध विकास में नेपाल की घरेलू बचत और उसे मिलने वाली विदेशी सहायता का निम्नतम अनुपात लगभग 45 प्रतिशत रहा है जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में उसकी घरेलू बचत से 75 प्रतिशत से अधिक उसे विदेशी आर्थिक सहायता प्राप्त हुई जिसमें भारत का योगदान 8.2 करोड़ रूपये का था जो कालान्तर में क्रमशः 11 करोड़, 55 करोड़, 56.3 करोड़, 64.3 करोड़ हो गया। नेपाल के योजनाबद्ध विकास में भारतीय योजनागत सहायता के साथ-साथ उस आर्थिक सहायता की भी चर्चा प्रासंगिक होगी जो भारत के द्वारा नेपाल को अनुदान के रूप में समय-समय पर उपलब्ध कराई जाती रहीं है। 31 मार्च 1990 तक भारत ने नेपाल को चार सौ बीस करोड़ की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई, जिसमें से नेपाल ने 377.89 करोड़ की सहायता प्रयुक्त कर ली। 1990-91 में 22.79 करोड़ रूपये की सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की गयी।<sup>3</sup>

भारत द्वारा नेपाल को विभिन्न मदों में दी गई आर्थिक सहायता<sup>4</sup>-

परियोजनाओं के नाम	प्रतिशत
पथ एवं हवाई अड्डे	60.9
उद्योग	1
डाक-तार	1.2
सामुदायिक योजना	2.7
सिंचाई, विद्युत एवं जल	26.7
योजना	5.3
कृषि	1
शिक्षा एवं स्वास्थ्य	1.2

भारत द्वारा नेपाल को प्रदत्त आर्थिक सहायता<sup>5</sup>-

सहायता क्षेत्र	सहायता की राशि (भारतीय मुद्रा)
पथ एवं हवाई अड्डे	200.50
संचार	1.60
शिक्षा	2.28
कृषि एवं बागवानी	1.20

सामुदायिक एवं पंचायत विकास	3.57
उद्योग	1.84
तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण	7.33
सिंचाई, विद्युत व जल	44.27

भारत प्रारम्भ से ही मानता रहा है कि आर्थिक रूप से समृद्धि उसके स्वयं के हितों की पूर्ति में सहायक हो सकती है।<sup>6</sup> इसलिए भारत ने नेपाल के नियोजित आर्थिक विकास पर ध्यान दे कर उसे प्रत्येक प्रकार का आर्थिक सहयोग प्रदान किया। नेपाल के साथ भारत का आर्थिक संबंध ब्रिटिश काल से ही था। 1923 की संधि में दोनों के आर्थिक संबंधों को एक औपचारिक आधार प्रदान करने का प्रयास किया गया। ब्रिटिश शासकों का नेपाल में प्रमुख हित अपने व्यापार को बढ़ाना था। अंग्रेजों ने एक प्रकार से यूरोपीय उत्पादों के लिए नेपाल के बाजार को खोला, परन्तु नेपाल का आर्थिक पिछड़ापन, राजाओं की कठोर आर्थिक नीति तथा जनसामान्य हितों के पूर्ति में रूचि न रखने के कारण यह व्यापार सीमित ही रहा। 1950 में भारत नेपाल शान्ति व मित्रता तथा व्यापार एवं पारगमन की संधि होने के पश्चात् भारत के नेपाल के साथ आर्थिक सहयोग ने एक नया मोड़ लिया।

भारतीय उद्योगपतियों तथा नेपाल के उद्योगपतियों द्वारा व्यक्तिगत (प्राइवेट) क्षेत्र में चलाये जा रहे सामूहिक उद्योगों का विवरण निम्न तालिका में द्रष्टव्य है-<sup>7</sup>

क्र. सं.	नेम ऑफ द इण्डियन कोलवोरेटर विद द अडरैस ऑफ ओवरसीज वैनर्स	सहयोग
1	मैसर्स ओबेराय होटल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता, ओए/मै. होटल सॉल्टी काठमाण्डू, नेपाल	होटल
2	मैसर्स हैदराबाद एसबैस्टर्स सीमेण्ट प्रोडक्ट्स लिमिटेड, हैदराबाद ओए/मै. नेपाल कम्पनी लिमिटेड थपाथली काठमाण्डू	खनिजों की खोज
3	मैसर्स आई.टी.सी. लिमिटेड (होटल डिवीजन) होटल मौर्य, नई दिल्ली	होटल
4	मैसर्स ओडिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड राउरकेला, ओए/मै. नेपाल ओरिण्ड मैग्नेसाइट (प्रा.) लिमिटेड, कांतीपथ, काठमाण्डू	माइनिंग ऑफ मैग्नेसाइट एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ रिफ़ैक्टरीज
5	मैसर्स कैमोकल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली	बनस्पति घी
6	मैसर्स यूनियन कारबाइड इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता	ड्राई बैटरीज
7	मैसर्स मोहन मीकिन्स लिमिटेड, नई दिल्ली, ओए/मैसर्स हिमालयन ब्रेवरी, काठमाण्डू	बीयर का उत्पादन एवं बोतलों में भरना
8	त्रिवेणी इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, नई दिल्ली	चीनी मिल
9	अपर गन्ना शुगर मिल्स, कलकत्ता, ओए/ओवरसीज एड्स	चीनी मिल

आज तक नेपाली विकास में भारतीय सहायता शीर्षस्थ है। नेपाल की जनसंख्या लगभग 20.6 मिलियन है। नेपाल के मुख्य उद्योगों में सीमेन्ट, इस्पात, सिगरेट, जूट, शक्कर, सूती, एवं सिन्थेटिक कपड़े, बिस्किट, चाय और साबुन आदि हैं। मुख्य कृषि

उत्पादन में खाद्यान्न के अतिरिक्त गन्ना, सोयाबीन प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त पर्यटन नेपाल का प्रमुख उद्योग है। भारत ने विकास के क्रम में नेपाल में पथ, परिवहन, उद्योग, संचार, कृषि विकास, जल विद्युत, ऊर्जा उत्पादन, शिक्षा आदि के क्षेत्र में प्रमुख रूप से सहायता दी है। उसका व्यापार भारत के साथ सकारात्मक है। इस सन्दर्भ में निम्न तालिका की सूचनाएं द्रष्टव्य हैं-<sup>8</sup>

प्रमुख उद्योग	सीमेंट 69.269 टन, स्टीलबार 28.409 टन, सिगरेट 6.24 विलियन स्टिक, जूट 16,00 टन, चीनी 32.030 टन, काटन टेक्सटाइल 4.09 मिलियन, सिन्थेटिक टेक्सटाइल 9.13 मिलियन, बिस्कुट 3.6 मिलियन टन, बीयर 5.03 मिलियन, साबुन 10,410 टन, चाय 898 टन।
प्रमुख कृषि	खाद्य उत्पादन 5.8 मिलियन टन, धान 3.4 मिलियन टन, मक्का 1.2 मिलियन टन, गेहूँ 850,000 टन, जौ 27,000 टन, ज्वार 225,000 टन, आलू 658,000 टन, तम्बाकू 7,000 टन, आयल सीड 100,000 टन, गन्ना 980,000 टन, सोयाबीन 7,280 टन, साइड्स 78,520 टन, नान साइड्स 405,463 टन, वनस्पति 967,000 टन, मीट 180,000 टन, अण्डे 3.2 मिलियन, मछली 19290 टन।
प्रमुख आयात	कुल आयात अमेरिकन डालर 613.37 मिलियन, फूड एवं लिब एनीमल 51.54 मिलियन, तम्बाकू एवं मंदिरा 9.5 मिलियन, खाने योग्य कच्चे पदार्थ 47.16 मिलियन, खनिज, ईंधन और लुब्रीकैंट्स 51.64 मिलियन, पशु एवं वनस्पति तेल एवं वसा 11.78 मिलियन, रासायनिक पदार्थ एवं इवाईया 108.7 मिलियन, मशीनरी, परिवहन सामग्री 100.38 मिलियन, निर्मित सामग्री 164.36 मिलियन।
प्रमुख निर्यात	कुल निर्यात अमेरिकन डालर 174.51 मिलियन डालर, फूड एवं लिब एनीमल 13.58 मिलियन, तम्बाकू और मंदिरा 4.97 मिलियन, कच्चा माल और खाद्य सामग्री 3 मिलियन, मशीन एवं परिवहन 33.3 मिलियन, रासायनिक पदार्थ एवं दवाईयां 366,000 मिलियन, अन्त्य निर्मित सामग्री 53.17 मिलियन, वगीकृत पदार्थ 90.75 मिलियन।
पर्यटन एवं यातायात	(1989) आगमन 239.945 कुल अभ्यागत व्यय 91.17 मिलियन।

नेपाल में भारत के सहयोग से कई पथ निर्मित हुए हैं जिनमें से कुछ पथ जैसे- महेन्द्र राजमार्ग, त्रिभुवन राजमार्ग आदि नेपाल की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। संचार के क्षेत्र में भैरवा, विराटनगर, जनकपुर, पोखरा और सिमरा वायुयान स्थल, काठमाण्डू का मुख्य डाकघर, नेपाल में लगी टेलीप्रिन्टर सेवा और भद्रपुर, जनकपुर धाम, विराटनगर, भैरवा, लोटी आदि स्थानों पर टेलीफोन सुविधाएं भारतीय सहायता का प्रयोग विकास परियोजनाओं के परिप्रेक्ष्य में हुआ है, इस सन्दर्भ में निम्न तालिका द्रष्टव्य है। विकासात्मक परियोजनाओं में भारतीय सहायता का उपयोग-<sup>9</sup>

विकासात्मक परियोजनाएं	सहायता राशि (भारतीय मुद्रा में)	सहायता राशि (प्रतिशत में)
पथ एवं वायुयान-स्थल	1005.0 लाख	61.8 प्रतिशत
विद्युत एवं सिंचाई	442.7 लाख	27.2 प्रतिशत
कृषि	12.6 लाख	0.8 प्रतिशत
उद्योग	18.4 लाख	2.5 प्रतिशत
संचार	16.0 लाख	1.0 प्रतिशत

कुल	1094.7 लाख	93.3 प्रतिशत
-----	------------	--------------

क्षेत्रवार सहायता का प्रयोग निम्न तालिका के अनुकूल किया गया है-

भारत की नेपाल को क्षेत्रगत सहायता<sup>10</sup>

सहायता क्षेत्र	सहायता राशि (भारतीय मुद्रा)	प्रयुक्त सहायता का प्रतिशत
पथ एवं वायुयान क्षेत्र	46.55 करोड़	53
डाक एवं तार	0.93 करोड़	1
सिंचाई, विद्युत व जलापूर्ति	29.32 करोड़	33
कृषि, बागवानी, पशुपालन व वन	1.07 करोड़	1
सामुदायिक व पंचायत विकास	3.43 करोड़	4
शिक्षा और स्वास्थ्य	0.73 करोड़	0.05
उद्योग	0.49 करोड़	0.05
अन्य योजनाएं	6.06 करोड़	7

भारत, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और विदेशी निवेश का स्रोत है। भारत नेपाल के लिए सबसे बड़ा गति प्रदान करने वाला राष्ट्र है। भारत का नेपाल के साथ सदैव सकारात्मक व्यापार सन्तुलन रहा है। भारत- नेपाल को आयात की अपेक्षा उसे निर्यात ज्यादा करता है। इसके विपरीत नेपाल ने भारत के साथ सदैव ऋणात्मक व्यापार सन्तुलन का सामना किया।

### 1. द्विपक्षीय ढाँचा-

भारत और नेपाल के बीच व्यापार की गतिशीलता के लिए एक द्विपक्षीय भारत-नेपाल संधि 1991 में की गयी 5 वर्षों के लिए वैध व्यापार संधि 3 दिसम्बर 1996 और 5 मार्च 2002 को पत्रों के आदान-प्रदान के द्वारा नवीनीकरण हुआ। व्यापारिक संधि के अन्तर्गत मार्च 2002 से भारत पारस्परिक आधार पर कर मुक्त सभी नेपाल निर्मित वस्तुओं के लिए भारतीय बाजार एक छोटी नकारात्मक सूची (सिगरेट, एल्कोहल, कॉस्मेटिक्स) स्थिति के अनुरूप इस प्रकार कि अनुमति प्रदान करता है, कि निर्यात 30 प्रतिशत घरेलू के साथ आवश्यकता की पूर्ति करेगा और नेपाल में निर्माण के क्रम में चार अंकों के स्तर पर एच.एस. वर्गीकरण में बदलाव लायेगा। मार्च 2002 की पुनरावृत्ति के बाद वसायुक्त वनस्पति (100, 000 टन), ऐक्राइलिक धागा (10,000 टन), तांबा उत्पाद (10,000 टन) और जिंक ऑक्साइड (2500 टन) जैसे चार संवेदनशील उत्पादों के लिए भारत के लिए कर मुक्त आयात हेतु वार्षिक आंकड़े वार्जित किए गए हैं।

द्विपक्षीय व्यापार सामान्यतः भारतीय रूपये में चलता है, लेकिन नेपाल का सेन्ट्रल बैंक उन वस्तुओं की सूची रखता है जो कि भारत से डालर में निर्यात की जा सकती है। वर्तमान में इस

सूची में लगभग 100 वस्तुएँ हैं। भारतीय रूपया नेपाल में वैध मुद्रा है और आसानी से (मुफ्त में) बदली जाती हैं। विनिमय दर भारतीय रूपये का 1.60 रूपये नेपाली रूपये में निर्धारित हो चुकी है।

मानक के लिए भारतीय ब्यूरो और नेपाल ब्यूरो और आन्तरिक विद्या के बीच भारत और नेपाल ने बहुपक्षीय सहयोग समझौते पर भी बातचीत की है।

गतिशीलता के लिए भारत- नेपाल संधि जो प्रत्येक सात वर्षों में नवीनीकृत की जाती है, नेपाल को कोलकाता तथा भारत नेपाल सीमा के लिए कोलकाता में पन्द्रह गतिशील मार्ग प्रदान किए हैं। नेपाल के अनुरोध करने पर 16 अगस्त 2004 से हल्दिया में एक अलग से जांच चौकी ने काम करना आरम्भ कर दिया। बहुपक्षीय व्यापार के लिए भारत-नेपाल सीमा के साथ-साथ 22 प्रवेश/निकास बिन्दु स्वीकृत किए जा चुके हैं। गतिशील संधि अंतिम बार मार्च 2006 में नवीनीकृत की गई थी। अनाधिकृत व्यापार को नियंत्रित करने के लिए भारत और नेपाल बीच सहयोग के लिए समझौता मार्च 2007 में पाँच वर्षों के लिए स्वतः नवीनीकृत हो गया।

दो सरकारें एक बहुपक्षीय निवेश रक्षा और दोनों देश पहले से ही सन 1987 से दोहरे कर से बचने का समझौता रखते हैं। भारत और नेपाल ने मई 2004 में एक रेल सेवा का विस्तार करने के लिए आई0सी0डी0, बीरगंज, नेपाल में एक रेल सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए। आई0सी0डी0 (इग्लैंड कन्टेनर डिपो) 17 मिलियन यू0एस0 डालर की विश्व बैंक की सहायता से निर्माण कर चुका है, जबकि भारत ने रेल मार्ग का निर्माण किया है, जो भारत में आई0सी0डी0 को रक्सौल रेलवे स्टेशन से जोड़ता है। आई0सी0डी0 का सेवा विस्तार 16 जुलाई 2004 को हुआ। यात्री वाहनों के लिए एक मोटर वाहन समझौता जो 23 फरवरी 2004 को हस्ताक्षरित हुआ, परन्तु अभी औपचारिक हस्ताक्षर का इंतजार है। आपसी समझौते के आधार पर भारत और नेपाल के बीच 14 मार्गों के द्वार पाँच सीमा बिन्दुओं के आधार पर विचाराधीन है। इस समझौते के अनुसार प्रतिदिन 53 बसे चलाई जायेंगी। अपने निजी वाहनों में किसी दूसरे देश के लिए व्यक्तिगत यात्रा बिना किसी अदायगी के पहले पांच दिनों हेतु भी उपलब्ध हो सकती है।

दो देशों की इंडियन एयरलाइन्स के सहयोग के साथ-साथ बहुपक्षीय सेवा समझौता नियम के अनुसार 1997 में हस्ताक्षरित दो देशों के लिए वायु सेवा समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। भारत के ओर से जो एयरवेज और जेटलाइट (एयर सहारा) और नेपाल की तरु से कोजमिक एयर ने भी दोनों देशों के बीच वायु सेवा को चलाया।

सीमा पार के व्यापार को सुधारने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बीरगंज-रक्सौल, बिराट नगर-जोगबानी, भैरवा-सोनौली और नेपालगेज-रूपैड़िया चार मुख्य जांच चौकिया स्थापित की गयी है। सम्बन्धों को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत ऑयल कारपोरेशन के साथ मिश्रित जोखम

के द्वारा रक्सौल और अमलेखगंज के बीच एक तेल पाइप लाइन बिछाई जा रही हैं। व्यापार पर एक अन्तः सरकारी समिति जिसका नेतृत्व वाणिज्य सचिवों द्वारा किया गया, भारत-नेपाल व्यापार में नीति नियमावली और मुद्दों पर विचार के लिए प्रतिवर्ष सम्पन्न की जाती है।

केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्री श्री आनन्द शर्मा और नेपाल के वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्री श्री राजेन्द्र महतो ने 27 अक्टूबर 2009 को भारत- नेपाल व्यापार सन्धि 2009 तथा अवैध व्यापार नियन्त्रण सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह सन्धि दोनों देशों के मध्य वर्ष 1996 की सन्धि का स्थान लेगी। इस सन्धि द्वारा भारत- नेपाल को कई छूट प्रदान करते हुए व्यापार के लिए कई मार्गों को खोलने को तैयार हुआ। श्री शर्मा ने इस सन्धि के विषय में कहा कि इस संशोधित व्यापारिक समझौते तथा नये मार्गों के खुलने से दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार और विस्तृत करने में मदद मिलेगी।<sup>11</sup>

हाल के वर्षों में नेपाल में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए तथा माओवादियों के नेपाल की राजनीति में पर्दापण के साथ भारत-नेपाल संबंधों पर भी प्रश्नचिह्न लग रहे थे। भारत के साथ नेपाल के पारस्परिक संबंधों को सुदृढ़ता प्रदान करने और विश्वास बहाली के लक्ष्यों के साथ नेपाल के माओवादी दल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री भारत की चार-दिवसीय राजकीय यात्रा पर रहे।

1. नेपाल के प्रधानमंत्री डॉ. बाबुराम भट्टराई ने भारतीय प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर अपनी पत्नी हिसिला यामी और एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 20-30 अक्टूबर 2011 के दौरान भारत की राजकीय यात्रा सम्पन्न की।
2. अगस्त 2011 के अंत में नेपाल के 35वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के बाद डॉ. भट्टराई की यह पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा थी।
3. इससे पूर्व दोनों देशों के प्रधानमंत्री 24 सितम्बर 2011 को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 66वें सत्र के दौरान मिले थे।
4. नेपाली प्रधानमंत्री 20 अक्टूबर 2011 को नई दिल्ली पहुंचे जहाँ अगले दिन राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया जिसके पश्चात हैदराबाद हाउस में उनकी भारतीय प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय एवं प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ताएं सम्पन्न हुईं।
5. इन वार्ताओं के दौरान प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा की तथा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ बहुलकीय संबंधों का और विस्तार एवं सवर्धन किए जाने पर सहमति व्यक्त की।
6. भारतीय प्रधानमंत्री ने नेपाल में शांति प्रक्रिया और संविधान निर्माण के संबंध में सर्वसम्मति का निर्माण किए जाने के प्रयासों का पूर्ण समर्थन किया।
7. दोनों प्रधानमंत्रियों ने वाणिज्य सचिवों की अन्तर्राष्ट्रीय समिति की बैठक शीघ्रातिशीघ्र बुलाने का निर्देश दिया, ताकि दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार एवं निवेश संबंधों को

सूदृढ़ बनाने के तौर तरीकों की पहचान की जा सके तथा व्यापार असंतुलन, व्यापार संधि के मुद्दों, 4 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क माफ करने संबंधी नेपाल के अनुरोध, कोलकाता-हल्दिया बंदरगाह एवं नेपाल के बीच भारतीय सीमा शुल्क विभाग द्वारा अतिरिक्त सीमा निर्धारण और नेपाल के व्यापार हेतु विशाखापट्टनम बंदरगाह को प्रचलित किए जाने सहित व्यापार एवं पारगमन से जुड़े सभी मुद्दों का समाधान किया जा सके।

8. नेपाल पक्ष ने सीमापार आपराधिक गतिविधियों के संदर्भ में भारत को आश्वस्त किया कि वह भारत विरोधी गतिविधियों के लिए अपने भू-क्षेत्र का उपयोग किए जाने की अनुमति नहीं देगा। दोनों पक्षों ने 'दोहरे कराधान के परिहार से संबद्ध करार' पर शीघ्रतिशीघ्र हस्ताक्षर करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की (भारतीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की 27 नवंबर 2011 की नेपाल यात्रा के दौरान इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर संपन्न हुए।)

9. नेपाल प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान भारत-नेपाल के मध्य तीन महत्वपूर्ण समझौते भी हस्ताक्षरित हुए।

#### हस्ताक्षरित समझौते/समझौते ज्ञापन-

##### 1. नेपाल में घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम के लिए भारतीय अनुदान से संबंधित समझौता ज्ञापन-

इसके तहत भारत नेपाल को घेंघा और आयोडीन की कमी से होने वाली अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए 1.875 करोड़ रूपये (3 करोड़ नेपाली रू०) उपलब्ध कराएगा। भारत द्वारा इस संदर्भ में 1973-2010 की अवधि में नेपाल को 41 करोड़ रू० की अनुदान सहायता उपलब्ध कराई गई है।

##### 2. नेपाल सरकार और भारत के आयात-निर्यात बैंक के मध्य डॉलर ऋण श्रृंखला करार-

इसके तहत भारतीय एक्जिम्बैंक नेपाल को 250 मिलियन डॉलर की ऋण-श्रृंखला उपलब्ध कराएगा जिसका उपयोग नेपाल में बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं हेतु किया जाएगा। इसकी रियायती ब्याज दर 1.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी और 5 वर्षों के स्थगन सहित इसका भुगतान 20 वर्षों की अवधि में किया जाएगा।

##### 3. नेपाल सरकार और भारत सरकार के मध्य निवेशों के संरक्षण पर करार-

इस करार में द्विपक्षीय निवेश प्रवाहों में वृद्धि करने के उद्देश्य से एक-दूसरे देश के भू-क्षेत्र में एक-दूसरे देश के निवेशों को संवर्धित एवं संरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत प्रत्येक देश में एक-दूसरे देश के निवेशों को राष्ट्रीय व्यवहार एवं एमएफएन व्यवहार प्रदान किया जाएगा अर्थात् निवेशों को उसी प्रकार का व्यवहार प्रदान किया जाएगा, जैसा व्यवहार उस देश के निवेशकों के साथ किया जाता है, अथवा किसी भी अन्य देश के निवेशकों के साथ किया जाता है। साथ ही इसमें निवेशों की वापसी के सन्दर्भ में भी एमएफएन व्यवहार प्रदान करने और आपात स्थिति में निवेशकों को हुए नुकसान को मुआवजा प्रदान करने का भी

प्रावधान किया गया है। यह करार प्रारंभ में 10 वर्षों की अवधि के लिए है तथा इसके पश्चात् इसका स्वतः विस्तार मान लिया जाएगा। बशर्ते कि दोनों में से एक पक्ष इसके विरोध में लिखित सूचना न दे दें।

1. इस यात्रा के दौरान डॉ. भट्टारई ने एसोचैम, सी. आई. आई. और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित व्यावसायिक बैठक को भी संबोधित किया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (यहीं से उन्हें पी.एच.डी. की उपाधि मिली थी।) में आयोजित एक कार्यक्रम में भी भाग लिया। वे देहरादून और हरिद्वार के दौरे पर भी गए।

##### 2. द्विपक्षीय व्यापार-

नेपाल के राजकर संबंधी 2005-06 (जुलाई से प्रारम्भ का द्विपक्षीय व्यापार 2.28 खरब था।) मिलियन था। भारत से नेपाल का आयात भारत की रकम का 1652.16 मिलियन था और भारत के साथ निर्यात औसतन 627.82 था। राजकर संबंधी वर्ष 2006-07 के दौरान भारत के कुल व्यापार 1.81 खरब था। भारत के लिए नेपाल का व्यापार लगभग 645.71 मिलियन था और भारत से आयात लगभग 1.81 विनियम था। जबकि भारत के लिए निर्यात लगभग 28 प्रतिशत तक बढ़ा। शेष संसार के लिए इसका निर्यात 0.9 प्रतिशत कम हुआ जबकि शेष संसार के आयात 10.3 प्रतिशत तक बढ़ा।

जब से नई व्यापार संधि पर 1996 में हस्ताक्षर किए गए तक से द्विपक्षीय व्यापार में शक्तिशाली वृद्धि हुई। चूंकि 1996 में भारत नेपाल व्यापार संधि के दोहराने से भारत के लिए नेपाल का निर्यात आठ गुना अधिक बढ़ा और कुल द्विपक्षीय व्यापार पाँच गुने से भी अधिक बढ़ गया है। सन् 1996 से नेपाल का कुल संसार में फैला हुआ निर्यात में 96 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी भारत के कारण ही हुई है।

1970 के प्रारम्भ में भारत ने नेपाल का लगभग सारा व्यापार अपने साथ मिला लिया था और नेपाल के आयात के लिए लगभग 90 प्रतिशत के लिए रकम लगाई। फिर भी नेपाल के विदेशी व्यापार में भारत का हिस्सा सन् 1990 तक 30 प्रतिशत तक नीचे गिर गया था। 1996 की संधि के समय से नेपाल के निर्यात में भारत का हिस्सा जुलाई 2007 (1995-96 में 18.50 प्रतिशत) 68.90 प्रतिशत तक बढ़ा है। नेपाल के आयात में भारत का हिस्सा जुलाई 2007 (1995-96 में 32.8 प्रतिशत) 61.4 प्रतिशत तक पहुँच गया। आज नेपाल के विदेशी व्यापार में भारत का लगभग दो तिहाई हिस्सा है।

भारत से नेपाल का मुख्य आयात पेट्रोलियम उत्पाद (29 प्रतिशत), मोटर वाहन और पुर्जे (8.3 प्रतिशत), एम.एस. पुर्जे (4 प्रतिशत), मशीनरी और पुर्जे (3 प्रतिशत), सीमेंट और रासायनिक उत्पादन है और दूसरे सह उत्पादक और मुख्य भोज्य उत्पादों की प्रगति पर निर्भर है। दूसरे मुख्य निर्यात, श्रृंगार संबंधी समान, सूत, दालें, पोलिस्टर धागे, इलायची, रेडिमेड वस्त्र आदि हैं। स्टील पट्टियाँ और चादर, भारत से आयातित कच्चा माल भी भारत के

लिए नेपाल से मुख्य आयात के रूप में उभरा है।

भारत की कम्पनियां नेपाल में सबसे बड़ी निवेशक हैं, रूपया 22.5 विलियन (यू. एस. डॉलर 346 मिलियन से थोड़ा अधिक) का कुल अनुमोदित प्रत्यक्ष निवेश का लगभग 44 प्रतिशत है और 1281 का 28.2 प्रतिशत विदेशी संग्रह के साथ साहसिक कार्यों के लिए भी है। सहयोगात्मक निवेश में चीन 12 प्रतिशत हिस्से के साथ दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है और जापान 10 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर है।

इन रुझानों को निम्न तालिकाओं द्वारा देखा जा सकता है-  
तालिका-1. भारत के साथ व्यापार नेपाली रूपया (यू.एस. डालर) मिलियन में-

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
कुल विदेशी व्यापार	1,91,866.0 (2603.6)	2,08,179.3 (2915.6)	2,34,014.4 (3188.2)	2,52,504.6 (3825.8)	2,86,903.5 (4412.5)
भारत के कुल व्यापार	1,12,896.2 (1,531.8)	1,27,952.4 (1,787.0)	1,47,857.8 (2,014.4)	1,59,615.2 (2,418.4)	1,83,150.5 (2,816.8)
कुल व्यापार में भारतीय साझेदारी	58.8 प्रतिशत	61.3 प्रतिशत	63.2 प्रतिशत	62.0 प्रतिशत	63.8 प्रतिशत
नेपाल का कुल निर्यात	52,723.7 (715.3)	58,705.7 (822.2)	60,234.1 (820.6)	60,795.8 (921.1)	60,787.5 (935.0)
भारत को कुल निर्यात	31,244.3 (423.9)	38,916.9 (545.0)	40,714.7 (554.6)	41,874.8 (634.0)	(594.0)
कुल निर्यात में भारतीय साझेदारी	59.2 प्रतिशत	66.3 प्रतिशत	67.6 प्रतिशत	70.3 प्रतिशत	63.5 प्रतिशत
नेपाल का कुल	1,39,142.3 (1,887.9)	1,39,142.3 (1,887.9)	1,73,780.3 (2,367.5)	1,97,708.8 (2,904.6)	2,26116.0 (3,477.6)
भारत से आयात	81,651.9 (1,107.8)	88,675.5 (1,241.9)	1,07,143.1 (1,459.7)	1,17,740.4 (1,783.9)	1,44524.1 (2,222.7)
कुल आयात में भारतीय हिस्सेदारी	58.6 प्रतिशत	59.3 प्रतिशत	61.7 प्रतिशत	59.5 प्रतिशत	63.9 प्रतिशत
कुल व्यापार संतुलन	-86,418.6 (-1,172.5)	-90,767.9 (-696.8)	-1,13,546.2 (-905.0)	-1,30,913.0 (-1,149.4)	-65,328.5 (-2,542.7)
भारत के साथ व्यापार संतुलन	-50,407.6 (-683.9)	-49,758.6 (696.8)	-66,428.4 (-905.0)	75,865.6 (-1149.4)	-1,05,897.7 (-1,628.6)
कुल व्यापार संतुलन में भारतीय हिस्सेदारी	58.3 प्रतिशत	54.8 प्रतिशत	58.5 प्रतिशत	54.8 प्रतिशत	64.1 प्रतिशत

तालिका-2. भारत के साथ व्यापारिक विकास (प्रतिशत में)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
नेपाल का कुल विदेशी व्यापार	9.1	9.5	12.4	8.4.6	12.9
भारत के साथ कुल व्यापार	12.5	16.5	15.9	6.6	16.2
कुल नेपाली निर्यात	8.0	8.9	2.6	-1.4	2.4
भारत को निर्यात	16.4	26.4	4.6	2.5	-7.4
कुल नेपाली आयात	9.6	9.7	16.3	12.0	16.1
भारत से आयात	11.0	12.6	20.8	8.1	24.7
कुल व्यापारिक संतुलन	10.7	10.2	25.1	19.2	22.2
भारत के साथ व्यापारिक संतुलन	7.8	3.7	33.5	11.6	42.3

2002 से 2008 तक का एकत्रीकरण							
	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2004-05
भारतीय निवेश	786.13	1,696.48	1,167.10	1,563.36	2,045.94	4,553.21	18,888.23
बढ़त प्रतिशत में	7.6	236	-31.2	34	30.8	122.5	31.7
उद्योगों की संख्या	280	10	15	31	28	37	401

नेपाल का गतिशील व्यापार कोलकाता/ हलदिया के बंदरगाहों के मार्गों के द्वारा तथा कोलकाता और भारत नेपाल सीमा के बीच 15 प्रतिष्ठित गतिशील मार्गों से होकर जाता है। बांग्लादेश के लिए नेपाल का व्यापारिक यातायात भी भारत से होकर ही गति करता है।

भारत और नेपाल ने अपने द्विपक्षीय व्यापार को और मजबूत करते हुए रविवार 27.11.2011 को एक संशोधित दोहरे करधान निवारण समझौते (डीटीए) पर हस्ताक्षर किए। काठमाण्डू में केन्द्रीय वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी और उनके नेपाली समकक्ष वर्षा मान पुन ने संशोधित कर समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह करार वर्ष 1987 में हुए समझौते की जगह लेगा। यह समझौता दोनों देशों के बीच बैंकिंग से जुड़ी जानकारी को एक दूसरे तक पहुंचाने में सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही भारतीय निवेशक और व्यापारी यदि नेपाल में एक बार अदा कर देते हैं तो उन्हें इस समझौते के तहत भारत में कर अदायगी से छूट होगी। इस अवसर पर मुखर्जी ने कहा कि विश्वास है कि यह व्यवस्था हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाएगी। हम आगे बढ़ने और अपने व्यापार एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों को विस्तार देने की स्थिति में होंगे। मुखर्जी ने कहा "यह समझौता आज के प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय माहौल को प्रदर्शित करता है और पुराने समझौते में सुधार की जरूरत है।" ज्ञात हो कि नेपाली प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई की अक्टूबर 2011 को

हुई भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय निवेश संरक्षण एवं संवर्धन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन कुछ मतभेदों के चलते दोहरे कराधान करार पर हस्ताक्षर नहीं हो सका। इस बीच दोनों देशों के प्रधानमंत्री जब इस महीने की शुरुआत में मालदीव में सार्क सम्मेलन से इतर मिले तो उनके बीच कराधान समझौते का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। उल्लेखनीय है कि नेपाल में विदेशी निवेश का भारत सबसे बड़ा स्रोत है और वर्ष 2010-11 में दोनों देशों के बीच 2.7 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार रहा है।<sup>12</sup>

भारत और नेपाल के द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने और दोनों देशों की सीमा से होने वाले अनाधिकृत व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए नई व्यापार संधि पर 2014 में हस्ताक्षर किए।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा यहां जारी वक्तव्य के अनुसार वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनन्द शर्मा तथा नेपाल के वाणिज्य मंत्री राजेन्द्र महतो ने काठमाण्डू में इस संधि पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर शर्मा ने कहा कि नए उत्पादों और भारतीय बाजार में उत्पादों की बिना शुल्क पहुंच के चलते दोतरफा व्यापार में काफी बढ़ोतरी होगी।

उन्होंने कहा कि यह संधि सात वर्षों तक लागू रहेगी और इसके तहत व्यापार केन्द्रों की संख्या 22 से बढ़ाकर 26 की जाएगी। उन्होंने कहा कि नए केन्द्रों में महेशपुर, सिक्ता विश्वबाजार, लौखा थाड़ी और गुलेरिया आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार तथा निवेश के अनुकूल माहौल को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।<sup>13</sup>

हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि भारत अपने पड़ोसी देशों विशेषकर नेपाल के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाने का सदैव ही प्रयास किया है। पिछले कई दशकों से व्यापार एवं पारगमन संधियां दोनों देशों के वाणिज्यिक संबंध को मजबूत बनाने तथा एक विशेष चरित्र प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किये हैं। इसके अतिरिक्त खुली सीमा, परिवहन, संचार, सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा वैश्विक बीमा आदि के संबंध में भारत नेपाल के बीच विशेष उपबन्ध तथा भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषाई व धार्मिक संबंध भी भारत नेपाल व्यापार को मजबूत आधार प्रदान किया है।

गोरे हो कि नेपाल के विदेश व्यापार का दो तिहाई भारत के साथ होता है जिसमें द्विपक्षीय व्यापार करीब 4.7 मिलियन डॉलर का है। वर्ष 1996 के बाद से भारत में नेपाल के निर्यात में 11 गुना की वृद्धि हुई है। इन सभी व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्तों के बीच भारत और नेपाल के बीच रिश्तों की डोर थोड़ी उगमगाने लगी थी, लेकिन मोदी की नेपाल यात्रा ने इस डोर को मजबूती प्रदान कर दौरे को सार्थक बना दिया।

3-4 अगस्त 2014 को अपने दौरे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेपाल को मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जो भारत के साथ किए गए समझौते में दिखती है। भारत नेपाल के बीच 3 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए जिससे यह साबित हुआ कि भारत कमजोर नेपाल की हर संभव मदद कर उसे मजबूत करना चाहता

है। उनकी यात्रा के दौरान 5,600 मेगावाट की पंचेश्वर बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर काम शुरू करने सहित दोनों पक्षों के बीच तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए। पहले समझौते के तहत भारत नेपाल को 690 करोड़ नेपाली रूपये की अनुदान सहायता देगा। इसके तहत नेपाल के ग्रामीण क्षेत्रों में आयोडीन युक्त नमक की आपूर्ति की जाएगी।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जलविद्युत सहयोग की क्षमता का लाभ प्राप्त करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो अलग-अलग मान्यताओं के कारण बहुत अधिक अछूता रहा है। वार्ता से भारत को उम्मीद है कि नया ऊर्जा करार संभव होगा जो इस क्षेत्र में दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद अवसरों के नए द्वार खोलेगा। यदि करार हो जाता है तो यह नेपाल में बार-बार पैदा होने वाले ऊर्जा संकट का समाधान करेगा और भारत भी करार के भाग के रूप में अतिरिक्त बिजली प्राप्त करेगा। विशेषज्ञों के अनुसार नेपाल में 40,000 मेगावाट हाइडल पावर है जो तकनीकी और वित्तीय रूप से व्यवहार्य पायी गई है। कुल हाइडल क्षमता 80,000 मेगावाट होने का अनुमान लगाया गया है। यदि नेपाल की जल-विद्युत क्षमता का अभीष्ट दोहन किया जाए तो यह दक्षिण एशिया का सबसे संपन्न दोष बनने की क्षमता रखता है।

इसलिए विकास भागीदारी के क्षेत्र को विस्तृत करना वह अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा जिस पर वार्ता के दौरान बल दिया गया। भारत ने इस हिमालयन राज्य के समावेशी विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को अनेक बार रेखांकित किया है और नेपाल सरकार को 100 मिलियन अमरीकी डॉलर तथा 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के दो आर्थिक ऋण पहले ही प्रदान कर दिये हैं।

विकास भागीदारी व्यापक क्षेत्रों में हुई है। इनमें भारत राजमार्गों, पुलों ऑप्टिकल फाइबर लिंको, मेडिकल कॉलेजों, ट्रामा सेंट्रो, पॉलीटेक्नीको, स्कूलों, अस्पतालो और स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कर रहा है। नदी प्रशिक्षण एवं तटबंध विनिर्माण के लिए भारत सरकार ने उदारता से निधियाँ और विशेषज्ञ सहायता प्रदान की है ताकि लालबकेया, बागमती और कमला नदियों के तटबंधों का सुदृढीकरण और विस्तार हो सके। इसके अलावा विद्युत पारेषण लाइनों के लिए एक 250 डॉलर का और दूसरा 125 डॉलर का एक्जिम बैंक ऋण प्रदान किया गया है। नेपाल के विभिन्न जिलों में चल रही लगभग 450 लघु विकास परियोजनाओं ने साधारण नेपाली जनता के लिए खुशियों का संसार बनाया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन का कहना है इनमें से कई परियोजनाओं की सफलता की कहानियाँ उल्लेखनीय हैं। जब हमने घेंघा परियोजनाओं को शुरू किया था तब उसे नेपाल को घेंघा से मुक्त करने के लिए शुरू किया गया था। 1985 में नेपाल में घेंघा लगभग 44 प्रतिशत लोगों को हो जाता था।

- Kathmandu: National Planning Commission Secretariat.
4. Cleland, J., and C. Wilson. 1987. Demand theories of fertility transition: An iconoclastic view.
  5. Population Studies 41(1): 5-30.
  6. Cohen, B. 2000. Family planning programs, socioeconomic characteristics, and contraceptive use in Malawi. World Development 28(5): 843-860.
  7. Isaacson, J.M., C.A. Skerry, K. Moran, and K.M. Kalavan. 2001. Half a century of development: The history of U.S. assistance to Nepal—1951-2001. Kathmandu: USAID.
  8. Jato, M.N., C. Simbakalia, J.M. Tarasevich, D.M. Awsum, C.N.B. Kihinga, and E. Ngrwamungu. 1999. The impact of multimedia family planning promotion on the contraceptive behaviour of women in Tanzania. International Family Planning Perspectives 25(2): 60-67.
  9. Kane, T.T., M. Gueye, I. Speizer, S. Pacques-Margolis, and D. Baron. 1998. The impact of a family planning multimedia campaign in Bamake, Mali. Studies in Family Planning 29(3): 309-323.
  10. Karki, Y.B. 1988. Sex preference and the value of sons and daughters in Nepal. Studies in Family Planning 19(3): 15-23.
  11. Kincaid, D.L. 2000. Social networks, ideation and contraceptive behaviour in Bangladesh: A longitudinal analysis. Social Science and Medicine 50(2): 215-231.
  12. Lawrence, R. 2000. Who is using modern methods of contraception in Malawi? Evidence from the Malawi Demographic and Health Survey 2000. Fact sheet No. 15. Southampton: Opportunities and Choices Program, University of Southampton.
  13. Ministry of Health (MOH) [Nepal]. 1999. Second long term health plan (1997-2017). Kathmandu: MOH.
  14. Ministry of Health (MOH) [Nepal]. 2004. Nepal health sector program—Implementation plan (NHSP-IP). 2004-2009. HMG/ Nepal: MOH.
  15. Ministry of Health (MOH) [Nepal] and Johns Hopkins University Population Communication Services (JHU/PCS). 1994. Nepal family planning communication survey (NFPCS): Key findings report. Kathmandu: MOH and JHU/PCS.
  16. Ministry of Health and Population (MOHP) [Nepal]. New ERA, and Macro International Inc. 2007.
  17. Nepal Demographic and Health Survey 2006. New ERA and Macro International Inc.
  18. National Health Education, Information and Communication Centre (NHEICC) [Nepal]. 2006. BCC/IEC desk review research. Kathmandu: Ministry of Health and Population.
  19. Piotrow, P., D.L. Kincaid, J.G. Rimon, and W. Rinehart. 1997. Health communication: Lessons learned from family planning and reproductive health. Westport, CT: Praeger.



संगोष्ठियों में शोध प्रपत्र का वाचन शोधार्थियों एवं शोधविदों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। अपने गुणवत्तापरक शोध कार्य को इन संगोष्ठियों के माध्यम से जनमन के बीच लाएं।

### पृष्ठ 60 का शेष

वर्ष 2007 में जब हमने इस परियोजना को समाप्त किया तब यह आंकड़ा घट कर 0.4 प्रतिशत रह गया। प्रशिक्षण के क्षेत्रों में भारत द्वारा 3000 नेपालियों को वार्षिक रूप से छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं।

संयुक्त आयोग की बैठक नेपाल के राजनैतिक पटल पर बदलाव के मध्य तब सम्पन्न हुई, जब संविधान-निर्माण की प्रक्रिया नया स्वरूप ले रही है। भारत ने नेपाल के आंतरिक मामलों से अपने को अलग रखने की सुविचारित नीति को बनाये रखा है, परन्तु हिमालयन राज्य में जो आधुनिकता और राष्ट्रीयता नवीकरण की अपनी यात्रा स्वयं की शर्तों पर तय कर रहा है। चिर शांति स्थायित्व लाने के लिए एक समावेशी राजनैतिक प्रक्रिया की निरंतर रूप से मैत्री भाव से वकालत की है। 27 मई को नई दिल्ली में प्रधान मंत्री कोइराला के साथ अपनी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल को “एक पुराने और बहुत ही सम्मानित मित्र” के रूप में वर्णित किया और ईमानदारी से उम्मीद जताई कि नेपाल द्वारा संविधान को एक वर्ष की उस समय-सीमा में अंगीकार कर लिया जाएगा जो उसने अपने लिए तय की है।

अतः भारत की विदेश मंत्री की 25-27 जुलाई 2014 की नेपाल तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3-4 अगस्त 2014 की नेपाल यात्रा भारत-नेपाल संबंधों को नए मार्ग पर लाने और दोनों पक्षों के लिए बहुआयामी लाभदायक अवसरों के असंख्य नए द्वार खोलने के लिए निर्णायक पल साबित हो सकता है, जिससे दोनों पड़ोसी देश खुशहाली के लिए मिलकर काम करते हुए और अधिक निकट आएंगे।

### सन्दर्भ:-

1. डॉ० एस० के० चतुर्वेदी, इडियाज रोल इन नेपाल डेवलपमेंट, फारेन अफेयर्स रिपोर्ट्स वाल्यूम- 35, न० 310, मार्च 1996, आई० सी० डब्ल्यू० ए०, नई दिल्ली, पृ०-74
2. ट्रेड एण्ड टेक्निकल डायरेक्ट्री, 1992
3. वही
4. डॉ० एस० के० चतुर्वेदी, भारत-नेपाल सम्बन्ध, बी० आर० पब्लिशिंग कारपोरेशन, दिल्ली 1993, पृ०-451
5. वही, पृ०-50
6. निर्मला अग्रवाल, भारत नेपाल सम्बन्ध, 1950 के शान्ति एवं मैत्री सन्धि के सन्दर्भ में एक अध्ययन, ए० बी० डी० पब्लिशर्स, जयपुर, 2003 पृ०-175
7. वर्कशाप आन ज्वाइंट वैचर्स एब्राड एण्ड प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स (रिपोर्ट) एफ० आई० सी० आई०, नई दिल्ली, 31 जुलाई 1982, अनेक्शर पृ०-75-77
8. एशिया 1991 वार्षिकी, पृ०-180
9. डॉ० कृष्णानन्द शुक्ल, भारत-नेपाल सम्बन्ध, अंकित पब्लिकेशन्स दिल्ली 2011, पृ०-229
10. वॉई० पी० पंत, प्राब्लम्स इन फिजिकल एण्ड मानिटरी पालिसी, पृष्ठ 61
11. दि हिन्दू 29 अक्टूबर, 2009
12. Indo Asian News Service, भारत-नेपाल ने किए कराधान समझौते पर हस्ताक्षर, 28 नवम्बर 2011
13. Web Dunia, भारत और नेपाल में नई व्यापार संधि, शुक्रवार, 01 दिसंबर 2014

